

निवेशकों को रास नहीं आया बजट

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट निवेशकों को लुभाने में विफल रहा और घरेलू शेयर बाजारों में रविवार को विशेष सत्र के दौरान शुरुआती तेजी के बाद भारी गिरावट देखी गयी।



सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़का
निफ्टी 495.20 अंक गिरा

बीएसई का सेंसेक्स 2,826 अंक के उतार-चढ़ाव के बाद अंत में 1,546.84 अंक (1.88 प्रतिशत) टूटकर चार महीने के निचले स्तर 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। बाजार बजट से पहले तेजी में था और एक समय 456 अंक चढ़कर 82,726.65 अंक पर पहुंच गया। लेकिन वित्त

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत की गिरावट में 24,825.45 अंक पर बंद हुआ। यह इसका भी चार महीने का निचला स्तर है। सूचकांक ऊपर 25,440.90 अंक और नीचे 24,571.75 अंक तक गया।



85 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कृषि, डेयरी, डिफेंस, हार्ड-स्पीड रेल कॉरिडोर और युवाओं के रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण एलान किए। इस बजट को सप्ताह के नेता आशाओं का बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे 'खाली' और अल्पविकसित बताते हुए आलोचना कर रहा है। विपक्ष की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और चुनौती दी कि 'कुछ ठोस बताइए कि क्या गलत है। क्या आप नहीं चाहते कि क्षेत्र आगे बढ़े, देश की उत्पादन क्षमता मजबूत हो, किसानों का भविष्य उज्ज्वल हो और टेक्नोलॉजी विकसित हो?'

किसानों के लिए 1.62 लाख करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश बजट 2026-27 में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े एलान किए। इस बार कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7% अधिक है। बजट का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, छोटे और मझोले किसानों को विशेष सहायता देना और ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करना है। सबसे बड़ा एलान किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का हुआ। अब ससिंडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे करोड़ों किसान, मछुआर और डेयरी व्यवसायी सस्ते ऋण के माध्यम से खेती और संबंधित व्यवसायों में निवेश कर सकेंगे। मत्स्य पालन और जल स्रोतों के विकास के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा और तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगा।



हरियाणा की अनदेखी

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट में हरियाणा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में हरियाणा की पूरी तरह अनदेखी की गई है और राज्य के साथ बार-बार हकमारी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब 'नायब' हो सरकार तो हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार-बार'। केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा बजट भाषण में हरियाणा का नाम भी नहीं लिया गया जो राज्य के साथ भेदभाव को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने बजट पर तंज कसते हुए कहा 'मिला राखी गद्दी में (एसएसआई) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इन्सुलुन'। श्री सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और बजट राज्य के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा।

त्वरित टिप्पणी

यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को मजबूत करता है

विकसित भारत का विजन, आम आदमी की दुविधा



डॉ ज्योति शर्मा
अर्थशास्त्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2026-27 सरकार की दीर्घकालिक सोच और आर्थिक अनुशासन को दर्शाता है। बजट में वित्तीय अनुशासन तारीफ के काबिल है, जहां वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रखा है और

बेवजह की मुफ्त योजनाओं का एलान नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बजट आम आदमी की मौजूदा परेशानियों का हल निकाल सकेगा या नहीं।

यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को मजबूत करता है पर जमीनी हकीकत पर इसकी पकड़ कुछ जगह कमजोर दिखाई देती है। निसंदेह यह बजट रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। एमएसएमई और निमाण क्षेत्र में निवेश स्वागत योग्य है। वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण, प्राकृतिक रेशों पर आधारित वस्त्रों का निर्माण, टेक्सटाइल इकोसिस्टम, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रमों को मजबूत

चौतरफा बिकवाली के बीच मझौली और छोटी कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.06 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.73 प्रतिशत गिर गया। एनएसई में आईटी सूचकांक की 0.57 प्रतिशत की तेजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर गिरावट में रहे। सार्वजनिक बैंकों का सूचकांक 5.57 प्रतिशत, धातु का 4.05 प्रतिशत, तेल एवं गैस का 2.86 प्रतिशत, एफएमसीजी का 2.29 प्रतिशत, रियलिटी का 2.22 प्रतिशत, ऑटो का 2.09 प्रतिशत और निजी बैंकों का 1.22 प्रतिशत की गिरावट में बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक और अडानी पोर्ट्स के शेयर साढ़े पांच प्रतिशत से ज्यादा टूट गये। बीईएल में भी सत्ता पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही। आईटीसी, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलएंडटी के शेयर तीन से चार प्रतिशत के बीच टूटे। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, मारुति सुजुको, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और महिंद्रा एंड महिंद्रा में दो से तीन प्रतिशत की गिरावट रही।

इंटरनल, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टैट और भारती एयरटेल के शेयर एक से दो प्रतिशत फिसल गये। एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर में भी करीब एक फीसदी की गिरावट देखी गयी।

टीसीएस का शेयर करीब दो प्रतिशत और इंफोसिस का एक प्रतिशत से अधिक चढ़ा। सनफार्मा और टाइटन के शेयर भी हरे निशान में रहे।

युवा और महिला शक्ति पर फोकस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और युवा विकास को केंद्र में रखते हुए कई बड़े प्रस्ताव रखे। उन्होंने बजट को 'युवा-शक्ति संचालित' और 'महिला-हितैषी' बताया और कहा कि यह कदम देश के विकास के हर कोने तक समान अवसर पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। बजट के रूप में यह पहल, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तीनों मोर्चों पर महिलाओं के लिए सशक्त बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। सबसे बड़ा एलान भारत के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल स्थापित करने का हुआ। सरकार का मानना है कि शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं — जैसे कि सुरक्षा चिंता, दूरी, और आर्थिक प्रतिबंध — को खत्म करने का यह एक प्रभावी उपाय है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ किशोर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है, वहां यह हॉस्टल योजनाएं सुरक्षित और समावेशी माहौल प्रदान करेंगी। बजट में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए SHE मार्ट्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है।



बदलाव लाने वाला बजट

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने बजट 2026-27 को शिक्षा और कौशल संस्कृति के लिए बदलाव लाने वाला करार दिया है। श्री चौधरी ने कहा कि 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर लेव्स नए क्रिएटिव करियर के रास्ते खोलेंगे। पांच विश्वविद्यालय ट्रांज़नशिप और एकेडमिक जोन के लिए सहयोग से क्षेत्रीय शिक्षा मजबूत होंगे। हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास छात्रों के लिए पहुंच और गरिमा पक्का करेगा। विदेश शिक्षा पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) दर पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि बजट में एमएसएमई के लिए दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे स्पोर्ट्स गुड्स की विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इससे मेरुट जैसे वलस्टर्स के लिए गेम-चेंजर होगा।

बच्चा गैंग फिल्म देखकर खिल उठे बच्चों के चेहरे

गरीब बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए आगे आये समाज सेवी

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 1 फरवरी. छिंदवाड़ा में प्रदर्शित फिल्म बच्चा गैंग को बच्चों पर आधारित फिल्म है जिसे देखने आज शासकीय माध्यमिक शाला परतला के बच्चे पहुंचे बच्चों को फिल्म देखाने के लिए समाजसेवियों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए शासकीय स्कूल में ध्यान रख बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वह 130 रुपए की टिकट कटा कर फिल्म देख सके लेकिन बच्चों की फिल्म को देखने की लालसा को देख गांधीगंज के समाजसेवी हेमंत मकड़ तथा स्कूल में कार्यरत शिक्षक मनीष भट्ट ने जिले के प्रतिष्ठित इंद्रजीत सिंह बैस से बच्चों को लाने ले जाने हेतु बस व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया तो उन्होंने त्वरित बच्चों के लिए बस की व्यवस्था उपलब्ध कराई शाला के कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार सिनेमाघर कैसा होता है



और बड़े पंटे पर फिल्म कैसे दिखाई देती है देखा।

शिक्षक मनीष भट्ट ने बताया कि फिल्म देखने के बाद जब बच्चों से फिल्म के विषय में चर्चा की गई तो प्रमुखित मन से बच्चों ने बहुत तारीफ की और बच्चों का मानना है की सभी पालकों को यह फिल्म अपने बच्चों के

साथ देखनी चाहिए।

लंबे समय के बाद बच्चों के लिए एक अत्यंत शिक्षाप्रद फिल्म के आने से बच्चों में अत्यंत उत्साह का माहौल है में जिले के समाज सेवियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी आगे आए और गरीब तबके के बच्चों को ये मुवी दिखाये।

सफलता की कहानी :मोहखेड़ के किसान कैलाश पवार ने पथरीली भूमि में जी-9 केले की खेती से रचा नवाचार

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 1 फरवरी. छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम भुताई के प्रगतिशील किसान कैलाश पवार ने नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है।

श्री पवार ने लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में केले की उन्नत किस्म जी-9 की खेती कर यह साबित कर दिया है कि कठिन मानी जाने वाली भूमि में भी आधुनिक तकनीक के सहारे बेहतर उत्पादन संभव है। उन्होंने गत वर्ष अप्रैल माह में पुणे से जी-9 किस्म के पौधे मंगवाकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ रोपण किया था, जो मात्र लगभग 11 माह में पूरी तरह तैयार होवाई है। किसान श्री पवार के अनुसार 15 फरवरी के बाद मार्च माह तक पूरी फसल की कटाई हो जाएगी और प्रति एकड़ ढाई से तीन लाख रुपये तक लाभ होने की संभावना है। फसल की गुणवत्ता को देखते हुए जबलपुर एवं नागपुर के व्यापारियों ने खेत

पर पहुंचकर निरीक्षण किया है तथा वे सीधे खेत से ही उपज खरीदने के लिए संपर्क कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यह केला पथरीली एवं मुरम वाली उस भूमि पर उगाया गया है, जहाँ सामान्यतः अन्य फसलें लेना संभव नहीं माना जाता। कृषि विभाग की टीम ने भी खेत पर पहुंचकर इस नवाचार का अवलोकन किया और किसान द्वारा अपनाई गई तकनीकों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि कैलाश पवार पूर्व से ही नवाचारी किसान रहे हैं। उन्होंने पिछले वर्ष लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित किया था। वर्तमान वर्ष में भी उन्होंने 6 एकड़ में स्ट्रॉबेरी, एक एकड़ में ब्लूबेरी तथा एक एकड़ में गोल्डन बेरी की खेती की है, जिसकी उपज 15 फरवरी के बाद बाजार में आने की संभावना है। कैलाश पवार की यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो यह संदेश देती हैं कि नवाचार, तकनीक और मेहनत के साथ कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है।



सोना-चांदी में भी देखने मिला उतार-चढ़ाव

बजट के दिन जहां देश की नजरें वित्त मंत्री के ऐलानों पर टिकी थीं, वहीं बुलियन मार्केट में ऐसा भूचाल आया जिसने निवेशकों को पूरी तरह चौंका दिया। केंद्रीय बजट 2026 पेश होते ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ा झटका चांदी ने दिया। कुछ ही दिनों पहले 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी, बजट के दिन फिसलकर 2.65 लाख रुपये तक आ गई। बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में 1,34,400 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे बाजार के जानकार ऐतिहासिक बता रहे हैं। निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा न होने से बाजार में निराशा फैल गई। शुक्रवार को ही चांदी के भाव में एक दिन में करीब 45,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि दो दिनों में कुल गिरावट 71,000 रुपये तक पहुंच गई। बजट से पहले निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को मौजूदा 6% से घटाकर 4% कर सकती है। हालांकि बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, जिससे बाजार में निराशा फैल गई और भारी बिकवाली देखने को मिली। इसी का असर चांदी की कीमतों पर सबसे ज्यादा पड़ा। एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी दोनों में दबाव देखा गया। बजट के दौरान सोने का भाव एक समय 6.45 फीसदी टूटकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली। वहीं चांदी की

गिरावट ज्यादा गहरी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती,

अभी जारी रहेगा। फिल्हाल इतना तय है कि बजट 2026 का यह दि-



4 लाख से फिसलकर 2.65 लाख पर पहुंचा सिल्वर सोने का भाव 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफावसूली चांदी की कीमतों में तेज गिरावट की बड़ी वजह रही। हालांकि कुछ जानकार इसे लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका भी मान रहे हैं। अब बाजार की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में चांदी खरीदारी करने वालों के लिए यह गिरावट का सिलसिला

चांदी निवेशकों के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा। डॉलर की मजबूती, वैश्विक संकेत और मुनाफावसूली के दबाव ने चांदी की गिरावट को और तेज कर दिया। जहां एक ओर निवेशकों को भारी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर खरीदारी करने वालों के लिए यह एक बड़ा मौका भी माना जा रहा है।



यह बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और अन्य जरूरतमंद समूहों के सशक्तिकरण की दिशा के अत्यंत प्रभावी होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठाकुर ने खेल क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन शुरू करने को लेकर कहा कि इससे जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। खेल विज्ञान और तकनीक का समावेशन होगा तथा खेल विकास संभव होगा।